Follow Us:- @newsroutine @newsroutine @newsroutine @newsroutine

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

E-mail: newsroutine6@gmail.com

✦वर्ष-05 ✦अंक-06 ✦जून -2026 ✦सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्रकाशित ✦पृष्ठ-32 ✦ मूल्य-35 रुपये

देश का सबसे बड़ा कोयला 'ग्रेड स्लिपेज' मूहाघोटाला

राजनांदगांव में विकास की ऐतिहासिक पहल
किसान समृद्धि की दिशा में मजबूत कदम

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक लागत के 333 विकास कार्यों की सौगात देकर जिले को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की समृद्धि, गांवों का समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए राज्य

में विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से राजनांदगांव जिले को फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और किसान समृद्धि के एक उभरते मॉडल के रूप में रेखांकित किया। किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ दलहन, तिलहन और अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि और जल संसाधनों का संरक्षण संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को फसल चक्र परिवर्तन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और अन्य किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही खेती के लिए आवश्यक खाद और बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

कृषक उन्नति योजना

खरीफ 2026 से लागू इस योजना के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन अथवा अन्य फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख विकास कार्य

राजनांदगांव जिले में सस्पेंशन ब्रिज निर्माण, शिवनाथ नदी क्षेत्र में एनीकट एवं संरक्षण कार्य, कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग निर्माण तथा अन्य आधारभूत परियोजनाएं शामिल हैं, जो क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेंगी।

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

RNI NO. CHHHIN/2022/83778
E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्रकाशित

प्रधान संपादक
गुलाब दास दीवान

सह- संपादक
जयदास मानिकपुरी

कानूनी सलाहकार
जवाहर पड़वार
इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय
न्यूज रूटीन
बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत
पवनी, जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय
सह- संपादक-**जयदास मानिकपुरी**
देव मेडिकल स्टोर के पास,हाउस नम्बर
55वार्ड नंबर- 04, साई राम चौक,
गोवर्धन नगर भनपुरी, रायपुर
मो. न. 62611,55546 छत्तीसगढ़- 492001

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुदक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णतः मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्रीः इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।
संपादक- गुलाब दास दीवान

वर्ष-05 | अंक- 06 | जून-2026

इस अंक में

2. आलाकमान का दबदबा कम हो गया है
3. योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
6. हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
8. जर्जर भवन के कारण एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर बच्चे
9. ग्राम सचिव पर रिश्वतखोरी के आरोप, ग्रामीणों ने जनदर्शन में की शिकायत
10. टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा: WHO और सेंट्रल टीबी डिविजन की टीम ने किया गुरूर का दौरा, कलेक्टर को सौंपी प्रगति रिपोर्ट
11. मोदी के नेतृत्व में समृद्ध व सशक्त भारत का निर्माण: सांसद संतोष पाण्डेय
13. बालोद में मिशन अंकुर की शुरुआत: 3.5 लाख सीड बॉल से बढ़ेगी हरियाली, कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने किया शुभारंभ
15. 'वन विभाग को रोशन' करने वाले को मिला 'अंधेरा'
18. मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा देश : नारायण चंदेल

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- **गुलाब दास दीवान,** द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित।
RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

आलाकमान का दबदबा कम हो गया है

सबसे बड़ा नेता या आलाकमान तो हर राजनीतिक दल मे होता है। यानी ऐसा नेता जिसने कुछ कह दिया,कर दिया तो उसका पालन करना ही होगा। पालन होता है तो माना जाता है कि आलाकमान का दबदबा है,सम्मान है,पार्टी में अनुशासन है, आस्था है, विश्वास है,भरोसा है कि आलाकमान जो कहता है या कहता है वह पार्टी हित में होता है, उससे ही पार्टी का भला हो सकता है।उसका विरोध कोई किसी तरह से नहीं करता है कोई करता है तो उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलती है क्योंकि यह आलाकमान की इज्जत की बात होती है। किसी भी वजह से आलाकमान की बात न मानी जाए,यह आलाकमान की बेइज्जती समझी जाती है। आलाकमान ने तय कर दिया कि कोई नेता किसी प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो इस पर हर हाल में अमल होना चाहिए,अमल हो तो माना जाएगा कि आलाकमान की बात मानी गई,आलाकमान की पार्टी में दबदबा है, नहीं मानी जाती है तो माना जाता है कि आलाकमान की दबदबा कम हो रहा है। राज्यसभा किस नेता को किस प्रदेश से भेजा जाना है,कांग्रेस में यह तय राहुल गांधी करते हैं। वही अघोषित आलाकमान है,वही अघोषित सबसे बड़े नेता है, उन्होंने तय कर दिया कि मप्र में मीनाक्षी नटराजन को राज्य सभा में भेजा जाना है।फिर तो यह मप्र के सब कांग्रेस नेताओं व संगठन की महती जिम्मेदारी है कि वह ऐसा करके दिखाए।ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि कांग्रेस के पास इसके लिए पर्याप्त संख्या बल था।इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं की किसी लापरवाही की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही कोई जानकारी न दिए के आधार पर रद्द कर दिया जाए तो यह कांग्रेस नेताओं की गलती मानी चाहिए लेकिन कांग्रेस के नेता इसके लिए भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं कि भाजपा ने शिकायत की नामांकन में कोई जरूरी जानकारी नहीं दी गई इसलिए नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन में यह जानकारी कैसे नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई और भाजपा को नहीं दी जाने वाली जानकारी किसने दी। माना जा रहा है कि यह जानकारी भाजपा को कांग्रेस के किसी नेता या नेताओं ने दी है ताकि भाजपा शिकायत करे और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो जाए। यानी मीनाक्षी मप्र से राज्यसभा में जा ही न सके। सीधी सी बात है कि कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि उनकी खास नेता मप्र से राज्यसभा में जाए और मप्र व तेलंगाना के कुछ कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी मप्र से राज्यसभा में जाए। क्योंकि उनसे कांग्रेस नेताओं की पुरानी खुन्नस है, मौका मिला और उन्होंने मीनाक्षी को बता दिया कि हम भी क्या कर सकते हैं। आलाकमान मीनाक्षी को राज्यसभा में चाहकर भी नहीं भेज सका और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चाहा कि मीनाक्षी राज्यसभा में न जा सके और वह अपनी कोशिश मे सफल रहे। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस में आलाकमान की बात आंखमुंदकर मानने वालों की संख्या राज्यों में कम होती जा रही है।कांग्रेस आलाकमान का मालूम है या बताने वालों ने बता दिया होगा कि मीनाक्षी राज्यसभा में नहीं जा सकीं तो उसके लिए कौन से कांग्रेस नेता दोषी है लेकिन आलाकमान जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं कर सकता क्योंकि इससे फजीहत तो आलाकमान की ही होनी है कि कांग्रेस में आलाकमान की बात भी अब मानी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला ऐसा मामला है जिससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस आलाकमान का दबदबा अब कम हो रहा है यानी राज्य के बड़े नेता वह नहीं कर रहे हैं जो आलाकमान चाहता है।इसकी शुरुआत केरल से देखी जा सकती है, आलाकमान केरल में सीएम वेणुगोपाल को बनाना चाहता था, इसके लिए दस दिन तक सतीशन पर हर तरह से मनाने का प्रयास किया गया लेकिन सतीशन नहीं माने और आलाकमान को मजबूरी में सतीशन को सीएम बनाना पड़ा। कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ कि आलाकमान जिसे सीएम बनाना चाहता था,वह नहीं बना,आलाकमान जिसे नहीं चाहता था वह सीएम बन गया।इसके बाद कर्नाटक में छह माह से सिध्दारमैया सीएम कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे जबकि आलाकमान चाहता था कि वह स्वेच्छा से सीएम की कुर्सी छोड़ दें। आलाकमान को कहना पड़ा तब सिध्दारमैया ने सीएम की कुर्सी छोड़ी और आलाकमान के वादे के अनुसार शिवकुमार सीएम बन सके। सिध्दारमैया ने कुर्सी छोडने. के बाद कहा भी आलाकमान के कहने पर कुर्सी छोड़ दिया हूं। लेकिन वह आलाकमान का यह कहना मानने से इंकार कर दिया कि वह दिल्ली की राजनीति करें और राज्य की राजनीति शिवकुमार को करने दें। उन्होंने आलाकमान से साफ कह दिया कि वह राज्य में ही रहेंगे और राज्य की राजनीति करेंगे यानी शिवकुमार को आने वाले दिनों में परेशान करते रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी कमजोर नेता हैं लेकिन हकीकत में पीएम मोदी तो पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के साथ ही गठबंधन के बड़े नेता है, देश के बड़े नेता हैं और विश्व के बड़े नेताओं में से एक हैं। पीएम मोदी की तुलना में राहुल गांधी तो इतने कमजोर नेता हैं कि अपनी पसंद की एक नेता को राज्यसभा में नहीं भेज पाते हैं कांग्रेस के कुछ नेता ही ऐसी साजिश करते हैं कि उनकी पसंद की नेता का नामांकन रद्द हो जाता है। वह राज्यसभा नहीं जा पाती है और राहुल गांधी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ है। वह हमेशा की तरह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगाते हैं, इस बार उनका आरोप है कि वोट चोरी,सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी के जरिए चुनाव के पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया गया है। भाजपा और चुनाव आयोग के रहते कांग्रेस के कई नेता राज्यों से राज्यसभा में गए हैं, इससे राहुल गांधी के आरोप में कोई दम नहीं रह जाता है कि मप्र में जो कुछ हुआ उसके लिए महज भाजपा दोषी है।

योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अम्बिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

अम्बिकापुर

अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत की सनातन परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो आज पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है, जो व्यक्ति को आत्मबल, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इस वर्ष की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली और बढ़ते तनाव के बीच योग हर आयु वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से सजग और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखता है। उन्होंने सभी लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि योग को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिलना योग की विश्वव्यापी स्वीकृति का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से बचाव में प्रभावी है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार कर रहा है। उन्होंने महर्षि पतंजलि के योगदान और भारतीय परंपरा में योग के महत्व का भी उल्लेख किया।

राज्य में योग के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योग को संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा, प्रशिक्षण और जनजागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बच्चों और युवाओं से विशेष रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में योग के प्रचार-प्रसार में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भी स्मरण किया गया। साथ ही जनजातीय युवाओं की शिक्षा और प्रगति के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

योग बना स्वस्थ जीवन का आधार

योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। नियमित अभ्यास से जीवनशैली से जुड़ी कई बीमारियों से बचाव संभव है।

वैश्विक मंच पर भारत की पहचान

योग आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है और स्वस्थ जीवन का संदेश फैल रहा है।

एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन

देश का सबसे बड़ा कोयला 'ग्रेड स्लिपेज' महाघोटाला!

खदान से निकला 'सोना', कागजों पर बना दिया 'कोयला'

अरबों रुपये डकार गया सरकारी सिंडिकेट!

क्यों मौन है केंद्रीय सूचना आयोग?

विशेष खोजी रिपोर्ट: मैगजीन ब्यूरो

देश के राजस्व को दीमक की तरह चाट रहे एक ऐसे संगठित और सुगठित 'प्रशासनिक सिंडिकेट' का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय से लेकर देश की शीर्ष सूचना एजेंसी केंद्रीय सूचना आयोग तक जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दीपका ओपनकास्ट खदान से शुरू हुआ यह 'ग्रेड स्लिपेज' घोटाला कोई साधारण वित्तीय हेराफेरी नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर देश के खजाने की ऐतिहासिक डकैती है, जिसे सरकारी फाइलों और निजी कंपनियों की साठगांठ से अंजाम दिया गया है।

क्या है 'ग्रेड स्लिपेज' का वह जादुई खेल, जिससे निजी घराने हुए मालामाल?

शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार साहू द्वारा आरटीआई और आधिकारिक दस्तावेजों से जुटाए गए प्रमाणों के अनुसार, यह खेल बड़े ही शातिराना ढंग से खेला जाता है:

कागजों पर उच्च ग्रेड का खेल: एसई-सीएल मुख्यालय के तत्कालीन निदेशक (तकनीकी/संचालन) आर. पी. ठाकुर द्वारा दीपका ओपनकास्ट खदान के कोयले का आधिकारिक ग्रेड G11 घोषित किया जाता है। इसी उच्च ग्रेड के आधार पर उपभोक्ताओं और निजी कंपनियों से एडवांस बुकिंग और भारी-भरकम राशि वसूली जाती है।

थर्ड पार्टी सैंपलिंग की आड़ में साजिश: जब यही उच्च गुणवत्ता वाला कोयला रेलवे, रोड और सेल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक

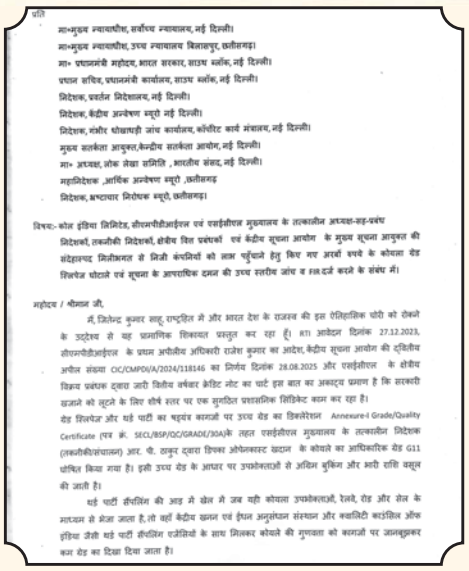

प्रति

मा॰मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

मा॰मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

मा॰ प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।

निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नई दिल्ली।

निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

मुख्य सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।

मा॰ अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, भारतीय संसद, नई दिल्ली।

महानिदेशक, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़

निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, छत्तीसगढ़।

विषय:- कोल इंडिया लिमिटेड, सीएमपीडीआईएल एवं एसईसीएल मुख्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों, तकनीकी निदेशकों, क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों एवं केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की संदेहास्पद मिलीभगत से निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने हेतु किए गए अरबों रुपये के कोयला ग्रेड स्लिपेज घोटाले एवं सूचना के आपराधिक दमन की उच्च स्तरीय जांच व FIR दर्ज करने के संबंध में।

महोदय / श्रीमान जी,

मैं, जितेन्द्र कुमार साहू, राष्ट्रहित में और भारत देश के राजस्व की इस ऐतिहासिक चोरी को रोकने के उद्देश्य से यह प्रामाणिक शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ। RTI आवेदन दिनांक 27.12.2023, सीएमपीडीआईएल के प्रथम अपीलीय अधिकारी राजेश कुमार का आदेश, केंद्रीय सूचना आयोग की द्वितीय अपील संख्या CIC/CMPDI/A/2024/118146 का निर्णय दिनांक 28.08.2025 और एसईसीएल के क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक द्वारा जारी वित्तीय वर्षवार क्रेडिट नोट का चार्ट इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि सरकारी खजाने को लूटने के लिए शीर्ष स्तर पर एक सुगठित प्रशासनिक सिंडिकेट काम कर रहा है।

ग्रेड स्लिपेज और थर्ड पार्टी का षड्यंत्र कागजों पर उच्च ग्रेड का डिक्लेरेशन Annexure-I Grade/Quality Certificate (पत्र क्रं. SECL/BSP/QC/GRADE/30A) के तहत एसईसीएल मुख्यालय के तत्कालीन निदेशक (तकनीकी/संचालन) आर. पी. ठाकुर द्वारा दिपका ओपेनकास्ट खदान के कोयले का आधिकारिक ग्रेड G11 घोषित किया गया है। इसी उच्च ग्रेड के आधार पर उपभोक्ताओं से अग्रिम बुकिंग और भारी राशि वसूल की जाती है।

थर्ड पार्टी सैंपलिंग की आड़ में खेल में जब यही कोयला उपभोक्ताओं, रेलवे, रोड और सेल के माध्यम से भेजा जाता है, तो वहाँ केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों के साथ मिलकर कोयले की गुणवत्ता को कागजों पर जानबूझकर कम ग्रेड का दिखा दिया जाता है।

खदान से उच्च श्रेणी (G11) का वास्तविक कोयला निकाला गया, लेकिन गंतव्य तक पहुँचते ही उसे घटिया घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के वास्तविक मूल्य और कागजों पर दिखाए गए कम मूल्य के अंतर का सीधा और नाजायज फायदा निजी औद्योगिक घरानों को पहुँचाया जाता है और बाद में करोड़ों रुपये वापस कर दिए जाते हैं।

वित्तीय अकाट्य प्रमाण अरबों रुपये का संदेहास्पद क्रेडिट नोट वितरण एसईसीएल दीपका क्षेत्र के क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक चार्ट से इस घोटाले का वास्तविक वित्तीय आकार उजागर होता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 CIMFR क्रेडिट अमाउंट =₹ 2,98,73,178.60 (दो करोड़ सत्तानवे लाख से अधिक) वित्तीय वर्ष 2016-17 CIMFR क्रेडिट अमाउंट =₹ 31,94,04,576.30 इतिहास में पहली बार अचानक छलांग मारकर सीधे इकतीस करोड़ से अधिक वित्तीय वर्ष 2018-19 CIMFR क्रेडिट अमाउंट = ₹ 1,27,93,56,741.98 तथा QCI क्रेडिट =₹ 12,47,75,164.94 अर्थात कुल मिलाकर ₹ 1.40 अरब से अधिक की राशि रिफंड की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 CIMFR क्रेडिट अमाउंट=₹ 73,08,60,447.79 तथा QCI क्रेडिट =₹ 11,46,83,441.39 अर्थात कुल मिलाकर ₹ 84 करोड़ से अधिक की राशि रिफंड की गई। जांच अधिकारियों के लिए वित्तीय विश्लेषण दीपका क्षेत्र के क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक के पत्र दिनांक 02.04.2024 (पत्र क्रं. SECL/GM/DA/AFM/24-25/03) से स्पष्ट है कि पहले यह राशि बिलासपुर मुख्यालय से समायोजित होती थी, लेकिन बाद में क्षेत्रीय स्तर से ही क्रेडिट नोट बनाकर राशि वापसी का प्रावधान कर दिया गया। बिना किसी उच्च स्तरीय फॉरेंसिक या भौतिक स्टॉक सत्यापन के, निजी कंपनियों के पक्ष में अरबों रुपये का यह रिफंड जारी करना सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुँचाई गई है।

इस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग एवं सीएमपीडीआईएल की आपराधिक संलिप्तता इस घोटाले को पूरी तरह छुपाने और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और सीएमपीडीआईएल को भी इस शिकायत में मुख्य रूप से घसीटा जाए।

मेरे द्वारा दिनांक 27.12.2023 को आरटीआई आवेदन देकर सीएमपीडीआईएल से खदानवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोयले के निरीक्षण के दौरान पाई गई वास्तविक गुणवत्ता व भंडारण का प्रमाणित रिकॉर्ड माँगा था। लेकिन सीएमपीडीआईएल के सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी राजेश कुमार ने चालाकी से पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से यह कहकर जानकारी छुपा ली कि अपेक्षित सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग का ढुलमुल रवैया और मौन संरक्षण जब यह मामला द्वितीय अपील संख्या CIC/CMPDI/A/2024/118146 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के समक्ष सुनवाई में आया दिनांक 28.08.2025, तो आयोग ने एक राष्ट्रीय घोटाले से जुड़े संवेदनशील माइनिंग डेटा को सुरक्षित कराने या भ्रष्ट अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय, प्रतिवादी पक्ष की इस दलील को आंख मूंदकर स्वीकार कर लिया कि सूचना स्पष्ट नहीं है और अपील को खारिज कर दिया।

केंद्र सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय के पेज 2 पर स्वयं स्वीकार किया कि प्रार्थी ने खानों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मांग की थी, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को बचाने के लिए यह लिख दिया कि रिकार्ड के आधार पर तथ्यात्मक जवाब प्रेषित कर दिया गया है, अतः आयोग के हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है। सूचना का यह प्रशासनिक दमन साबित करता है कि केंद्र सूचना आयोग के शीर्ष स्तर से लेकर कोयला विभाग के अधिकारियों तक सब मिलकर इस सिंडिकेट की चोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस सुनियोजित घोटाले को अंजाम देने और शासकीय पदों का दुरुपयोग करने वाले निम्नलिखित तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध नामजद आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

1. तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता मुख्यालय।
2. तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, SECL मुख्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
3. तत्कालीन निदेशक (तकनीकी / संचालन), आर. पी. ठाकुर, SECL मुख्यालय, बिलासपुर।
4. तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी राजेश कुमार, केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड, रांची।
5. तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक / क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक / क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, SECL, दीपका क्षेत्र।
6. मा॰ मुख्य सूचना आयुक्त (हीरालाल सामरिया) एवं उप-पंजीयक (एस. के. चिटकारा), केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

अतः माननीय न्यायालयों एवं देश की शीर्ष जांच एजेंसियों से विनम्र प्रार्थना है कि इस राष्ट्रीय महत्व और राजस्व चोरी के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर स्वयं संज्ञान लें। ED, SFIO और CBI को निर्देशित किया जाए कि वे कोल इंडिया, एसईसीएल, सीएमपीडीआईएल के उक्त तत्कालीन सीएमडी, तकनीकी निदेशकों, क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों और केंद्रीय सूचना आयोग के संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करें।

वर्ष 2015 से लेकर अब तक दीपका क्षेत्र द्वारा जारी किए गए समस्त क्रेडिट-डेबिट नोट्स और शून्य रॉयल्टी वाले इनवॉइस का कैग से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इस घोटाले से अर्जित की गई राशि की रिकवरी हेतु दोषी अधिकारियों और लाभान्वित निजी कंपनियों की संपत्तियों को PMLA कानून के तहत तुरंत कुर्क किया जाए।

मैं राष्ट्रहित में और भारत देश के राजस्व की इस ऐतिहासिक चोरी को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यह शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके त्वरित हस्तक्षेप से भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे देश में इस ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की मिसाल कायम होगी। इस कार्रवाई में मेरे द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिए तत्पर रहूंगा।

आवेदक
जितेंद्र कुमार साहू
C/O:-पथर्री पारा, साहू बस्ती वार्ड क्रमांक 17,
विद्युत गृह स्कूल के पास कोरबा,
जिला:- कोरबा (छ.ग.) 495677
मो॰ नं॰:- 9179697845,83192 71061

भेजा जाता है, तो वहाँ केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़ा खेल होता है।

सोना बना दिया मिट्टी: खदान से निकला उच्च श्रेणी G11 का वास्तविक कोयला गंतव्य तक पहुँचते ही कागजों पर 'घटिया और कम ग्रेड' का घोषित कर दिया जाता है।

घोटाले का मुख्य सूत्र: उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के वास्तविक मूल्य और कागजों पर दिखाए गए कम मूल्य के इसी अंतर का सीधा और नाजायज फायदा बड़े-बड़े निजी औद्योगिक घरानों को पहुँचाया जाता है और बाद में 'क्रेडिट नोट' के नाम पर उन्हें अरबों रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। खदान से 'सोना' निकला, लेकिन निजी कंपनियों की तिजोरी भरने के लिए उसे कागजों पर 'कोयला' बता दिया गया!

अकाट्य प्रमाण: आंकड़ों की बाजीगरी, जो चीख-चीख कर कह रही है 'घोटाला हुआ है'

दीपका क्षेत्र के क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक चार्ट से इस घोटाले का जो वित्तीय आकार सामने आया है, वह होश उड़ाने वाला है:

। वित्तीय वर्ष । एजेंसी / माध्यम । रिफंड / क्रेडिट की गई राशि (रुपये में) ।

2015-16 CIMFR क्रेडिट अमाउंट । 2,98,73,178.60 (दो करोड़ सत्तानवे लाख से अधिक) ।

2016-17 । CIMFR क्रेडिट अमाउंट । 31,94,04,576.30 (इतिहास में पहली बार अचानक छलांग) ।

2018-19। CIMFR + QCI क्रेडिट । 1.40 अरब से अधिक (1,27,93,56,741.98 + 12,47,75,164.94) ।

2020-21। CIMFR + QCI क्रेडिट । 84 करोड़ से अधिक** (73,08,60,447.79 + 11,46,83,441.39) ।

क्षेत्रीय स्तर से ही मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता साफ!

दीपका क्षेत्र के क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक के पत्र दिनांक 02.04.2024 से खुलासा हुआ है कि पहले यह राशि बिलासपुर मुख्यालय से समायोजित होती थी, लेकिन बाद में क्षेत्रीय स्तर से ही क्रेडिट नोट बनाकर राशि वापसी का चोर रास्ता तैयार कर दिया गया। बिना किसी उच्च स्तरीय फॉरेंसिक या भौतिक स्टॉक सत्यापन के, निजी कंपनियों की झोली में अरबों रुपये का यह रिफंड डालना सीधे तौर पर देश के साथ गद्दारी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संदेहास्पद भूमिका: जब रक्षक ही बन गया भक्षक!

इस महाघोटाले का सबसे स्याह पहलू यह है कि जब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार का सहारा लिया गया, तो देश की सर्वोच्च सूचना इकाई ने ही इस पर पर्दा डाल दिया।

जानकारी छुपाने की चालाकी: जब सीएमपीडीआईएल से खदानवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोयले के भंडारण का प्रमाणित रिकॉर्ड माँगा गया, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी राजेश कुमार ने यह कहकर जानकारी छुपा ली कि ₹सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त का ढुलमुल रवैया: जब यह संवेदनशील मामला द्वितीय अपील संख्या CIC/CMPDI/A/2024/118146 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के समक्ष सुनवाई में आया दिनांक 28.08.2025, तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्व से जुड़े माइनिंग डेटा को सुरक्षित कराने या भ्रष्ट अधिकारियों पर डंडा चलाने के बजाय, प्रतिवादी पक्ष की दलील को आंख मूंदकर स्वीकार कर लिया और अपील को खारिज कर दिया। यह सूचना का आपराधिक दमन साफ साबित करता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के शीर्ष स्तर से लेकर कोयला विभाग के अधिकारियों तक, सब मिलकर इस सिंडिकेट की चोरी को छुपाने में लगे हैं।

घोटाले के वे 'मुख्य किरदार' जिनके खिलाफ नामजद FIR की मांग

इस सुनियोजित घोटाले को अंजाम देने और शासकीय पदों का दुरुपयोग करने वाले जिन तत्कालीन अधिकारियों को इस शिकायत में सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया है, वे हैं:

1. तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता

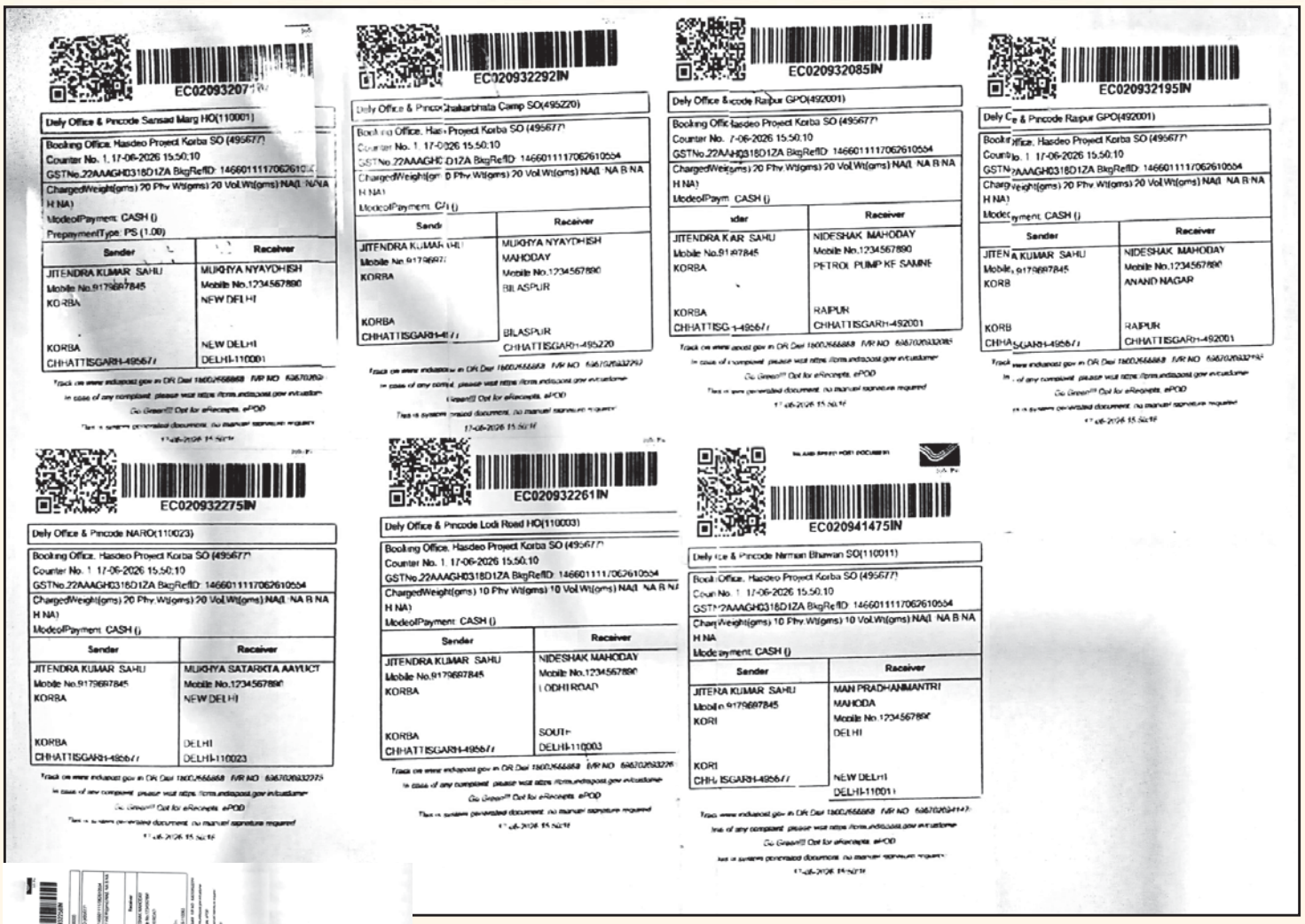

मुख्यालय।

2. तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, SECL मुख्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
3. तत्कालीन निदेशक (तकनीकी/संचालन), आर. पी. ठाकुर, SECL मुख्यालय, बिलासपुर।
4. तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी राजेश कुमार, CMPDI, रांची।
5. तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक / क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक / क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, SECL, दीपका क्षेत्र
6. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त (हीरालाल सामरिया) एवं उप-पंजीयक (एस. के. चिटकारा) केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

अब क्या करेगी सरकार? ED, CBI और SFIO की साख दांव पर!

शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार साहू ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय), प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय , केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो , और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को शिकायत भेजी है।

मुख्य मांगें

वर्ष 2015 से लेकर अब तक दीपका क्षेत्र द्वारा जारी किए गए समस्त क्रेडिट-डेबिट नोट्स और शून्य रॉयल्टी वाले इनवॉइस का कैग से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।

दोषी अधिकारियों और लाभान्वित निजी कंपनियों की संपत्तियों को PMLA कानून के तहत तुरंत कुर्क*किया जाए।

सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

तीखा सवाल

> जब देश का एक आम नागरिक राष्ट्रहित में अपनी जान हथेली पर रखकर अरबों रुपये की इस ऐतिहासिक चोरी के पुख्ता सबूत सामने ला रहा है, तो देश की संसद और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बैठे जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस प्रशासनिक सिंडिकेट को ध्वस्त करने का साहस दिखाएंगे? जनता देख रही है!

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में आर्थिक संकट से उबरने के लिए दी जाने वाली राहत है, जिसे केवल निर्धारित नीति और नियमों के तहत ही प्रदान किया जा सकता है।

मामले की सुनवाई करते हुए रमेश सिन्हा और रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर स्पष्ट किया नियम

क्या है मामला?

मामला धमतरी जिले के कुरुद तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 स्वर्गीय अशोक कुमार रंगारी से जुड़ा है। उनका 5 नवंबर 2024 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। निधन के बाद उनके पुत्र हेनरी रंगारी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक का बड़ा पुत्र एवं हेनरी का सौतेला भाई वीरेंद्र बहादुर रंगारी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है और जगदलपुर में पदस्थ है। इसी आधार पर जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति ने आवेदन निरस्त कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी?

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में तर्क

दिया गया कि वीरेंद्र बहादुर रंगारी वर्ष 2006 से परिवार से अलग रह रहे हैं और मृतक कर्मचारी के परिवार का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए उनके सरकारी सेवा में होने का लाभ या प्रभाव अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और राज्य सरकार की नीति का परीक्षण करने के बाद इस दलील को स्वीकार नहीं किया और समिति के निर्णय को उचित माना।

अदालत की अहम टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह नियमित नियुक्ति का विकल्प नहीं है और न ही इसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है। यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से शासकीय सेवा में है, तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों में सरकार की निर्धारित नीति का पालन अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने नियुक्ति निरस्तीकरण को ठहराया सही

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उसी राज्य में मिल सकता है, अभ्यर्थी जहां का मूल निवास है। कोर्ट ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया के मामले में एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कलेक्टर कोरिया के आदेश को सही ठहराया है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच में हुई। दरअसल, कोरिया जिले में 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTG) के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हुई थी। आवेदिका रामवती ने भृत्य पद के लिए आवेदन किया था। चयन के बाद उसे 8 अगस्त 2022 को नियुक्ति भी दे दी गई। हालांकि बाद में दस्तावेजों की जांच हुई, तो पता चला कि महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली है और उसका जाति प्रमाण पत्र भी वहीं के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इसे आधार बनाकर कलेक्टर कोरिया ने 27 अक्टूबर 2022 को उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। कोरिया कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए रामवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई। जिसमें कलेक्टर की कार्रवाई और आदेश पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर ने उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का सीधेतौर पर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना था कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही उसकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए उसे बहाल किया जाए।

कोर्ट का निर्णय-सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आवेदिका एक जनजातीय समूह से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का है, जिसे छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं किया जा सकता। आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में लिया जा सकता है, जहां संबंधित व्यक्ति का जन्म हुआ हो या वह मूल निवासी हो।

शाला प्रवेश महोत्सव के बीच नौरंगपुर स्कूल की बदहाल तस्वीर

जर्जर भवन के कारण एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर बच्चे

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़-नौरंगपुर

शिक्षा के दावों पर सवाल! नौरंगपुर प्राथमिक स्कूल का भवन खस्ताहाल, जोखिम के बीच पढ़ाई कर रहे नौनिहाल।

प्रदेशभर में शाला प्रवेश महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नए विद्यार्थियों का स्वागत हो रहा है, किताबें बांटी जा रही हैं और शिक्षा के महत्व पर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन आयोजनों के बीच जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है।

सारंगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला नौरंगपुर की स्थिति शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर बयां कर रही है। स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें हैं और भवन की स्थिति ऐसी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। बरसात शुरू होने के साथ ही यह चिंता और बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के छात्र-छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं। मुख्य भवन की खराब स्थिति को देखते हुए बच्चों को एक अतिरिक्त कक्ष में बैठाया जा रहा है। लेकिन वहां केवल एक ही कमरा उपलब्ध होने के कारण सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जर्जर भवन की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ऐसे में बच्चों को जोखिम के बीच शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है।

उठ रहे बड़े सवाल

जब शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई जाती है तो जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही? करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के दावों के बावजूद स्कूलों की मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं सुधर रहीं?

क्या शाला प्रवेश महोत्सव केवल औपचारिक आयोजन बनकर रह गया है?

बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उन्हें सुरक्षित भवन उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है?

नौरंगपुर स्कूल की यह स्थिति केवल एक विद्यालय की समस्या नहीं, बल्कि उन दावों पर भी सवाल खड़े करती है जिनमें शिक्षा को विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया जाता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा एवं बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए कब तक ठोस कदम उठाते हैं।

ग्राम सचिव पर रिश्वतखोरी के आरोप, ग्रामीणों ने जनदर्शन में की शिकायत

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़-बिलाईगढ़

जिले की ग्राम पंचायत मुड़पार-एस में ग्राम सचिव के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। उपसरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत सौंपकर सचिव पर रिश्वत मांगने, पद के दुरुपयोग और शासकीय कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार पेंशन स्वीकृति, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसे सरकारी कार्यों के लिए ग्रामीणों से पैसे मांगे जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना राशि दिए कई मामलों में कार्य नहीं किए जाते।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सचिव पंचायत भवन में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते और कई बार लोगों को अपने निजी निवास पर बुलाकर काम करते हैं। इससे विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि राशन कार्ड, पेंशन एवं अन्य प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग राशि की मांग की गई। ग्रामीणों ने सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद विकास कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सचिव को पंचायत से हटाने तथा कथित भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

जनदर्शन में शिकायत प्राप्त होने के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना शेष है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा: WHO और सेंट्रल टीबी डिविजन की टीम ने किया गुरूर का दौरा, कलेक्टर को सौंपी प्रगति रिपोर्ट

निरीक्षण, CHC गुरूर में टीबी जांच और उपचार व्यवस्थाओं का लिया जायजा

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा: WHO और सेंट्रल टीबी डिविजन की टीम ने किया गुरूर का दौरा, कलेक्टर को सौंपी प्रगति रिपोर्ट

न्यूज रुटीन @ बालोद/गुरुर

देश को क्षय रोग (टीबी) से मुक्त करने के उद्देश्य से संचालित ₹टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय अभियान (गांव-गांव शहर-शहर)₹ के अंतर्गत आज सेंट्रल टीबी डिविजन (CTD) और राज्य स्तरीय विशेष टीम द्वारा विकासखण्ड गुरूर का सघन दौरा किया गया। इस दौरान टीम ने क्षेत्र में आयोजित विशेष शिविरों का भ्रमण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) गुरूर का विजिट कर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की जमीनी हकीकत व व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

केंद्रीय और राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति

इस उच्च स्तरीय निरीक्षण दल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे। सेंट्रल टीबी डिविजन से डॉ. वीना धवन (अतिरिक्त आयुक्त, CVAC और CTD), डॉ. राधा तरालेकर (भारत सरकार-WHO राष्ट्रीय सलाहकार) एवं डॉ. ज्योति कायस्थ (भारत सरकार-WHO राष्ट्रीय सलाहकार), और श्री राजन चौहान (वित्त सलाहकार, CTD) विशेष रूप से उपस्थित रहे।

राज्य टीबी सेल की ओर से डॉ. मनीष मसीह (WHO सलाहकार), डॉ. रोचक सक्सेना (WHO सलाहकार), श्री निशांत मेश्राम (माइक्रोबायोलॉजिस्ट), डॉ. रेणुका प्रसन्नो (प्रभारी, STDC) और श्रीमती दीक्षा पुरी (सलाहकार, PMTBMA) शामिल थीं। स्थानीय स्तर पर जिला क्षय अधिकारी डॉ. जी. आर. रावटे एवं जिला टीबी उन्मूलन टीम ने विजिट के दौरान समन्वय किया।

कलेक्टर से शिष्टाचार मुलाकात और रणनीतिक चर्चा

विजिट के उपरांत संयुक्त टीम ने बालोद जिला कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा से सौजन्य मुलाकात की। टीम ने कलेक्टर को जिले में चल रहे 100 दिवसीय अभियान की गतिविधियों, मरीजों की खोज (Active Case Finding), और उपचार की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने टीम के सुझावों की सराहना करते हुए जिले को पूर्णतः टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग और कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया।

शिविरों और सीएचसी गुरूर का निरीक्षण

सेंट्रल टीम ने गुरूर विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए शिविरों में पहुंचकर मरीजों की जांच, काउंसिलिंग और दवाओं के

वितरण की व्यवस्था देखी। इसके बाद सीएचसी गुरूर के निरीक्षण के दौरान टीम ने टीबी जांच प्रयोगशाला (Lab), डॉट्स (DOTS) सेंटर और मरीजों के रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया। टीम ने जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (मितानिन और एएनएम) का उत्साहवर्धन किया और उन्हें टीबी के लक्षणों वाले संभावित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करने के निर्देश दिए।

मोदी के नेतृत्व में समृद्ध व सशक्त भारत का निर्माण: सांसद संतोष पाण्डेय

न्यूज रुटीन @ बालोद

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद Santosh Pandey संतोष पाण्डेय बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की विभिन्न जनकल्याण-कारी योजनाओं, विकास कार्यों, आर्थिक सुधारों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक देश का नेतृत्व करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल विकास, विश्वास और जनकल्याण का स्वर्णिम काल रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ₹प्रधान सेवक₹ मानते हैं और देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार समझकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों बैंक खाते खोले गए, जबकि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, जबकि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता अभियान को नई दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

सांसद ने कहा कि लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।

सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय चेतना का उल्लेख

मीडिया संवाद के दौरान सांसद पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को भी नई पहचान दी है। कर्तव्य पथ,

किसानों और जनजातीय समाज के लिए योजनाओं का उल्लेख

संतोष पाण्डेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने जनजातीय समाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष बजट प्रावधानों और ₹धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान₹ का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

पंचतीर्थ, जनजातीय गौरव दिवस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नए संसद भवन और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हुए आधुनिक विकास की ओर अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार

संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेलवे परियोजनाओं, किसान हितैषी योजनाओं और उड़ान योजना के माध्यम से व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में लाखों आवासों का निर्माण किया गया है तथा रेलवे और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़े निवेश किए जा रहे हैं।

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा

सांसद ने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में उभरा है। जी-20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री अभियान और बढ़ते विदेशी निवेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय का भारत पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है।

भाजपा की राजनीतिक उपलब्धियों का भी किया उल्लेख

मीडिया संवाद के दौरान सांसद पाण्डेय ने कहा कि भाजपा ने ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक लगातार जनसमर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों में भाजपा सरकारें विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही हैं और केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाने का कार्य किया है।

कार्यक्रम में भाजपा के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें यज्ञदत्त शर्मा, देवलाल ठाकुर, अभिषेक शुक्ला, कृष्णकांत पवार, राकेश यादव, वीरेंद्र साहू, राकेश छोटू यादव, हरीश कटझरे, प्रेम साहू, जितेंद्र साहू, विनोद जैन, कमल पनपालिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

खरीफ 2026 की तैयारियां मजबूत: दुर्ग संभाग में किसानों के लिए खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण

कृषि विभाग की व्यापक तैयारी, समय पर उपलब्ध होंगे उर्वरक और गुणवत्तायुक्त बीज

किसानों के लिए राहत भरी खबर: खरीफ सीजन से पहले खाद-बीज की पूरी व्यवस्था

जमाखोरी और कालाबाजारी पर नजर, दुर्ग संभाग में खाद-बीज आपूर्ति की सतत निगरानी

न्यूज रुटीन @ बालोद

खरीफ सीजन 2026 को सफल और उत्पादक बनाने के लिए दुर्ग संभाग में कृषि विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरकों एवं बीजों का पर्याप्त भंडारण किया गया है, जिससे खेती-किसानी के कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकें। दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में कृषि गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष किसानों को बड़ी मात्रा में उर्वरकों का वितरण किया गया था और इस वर्ष भी मांग के अनुरूप पर्याप्त स्टॉक एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

वर्तमान में यूरिया, डीएपी, एसएसपी, पोटाश तथा एनपीके सहित विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कृषि विभाग ने सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, निजी विक्रेताओं और विपणन संस्थाओं के माध्यम से वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया है। बड़ी मात्रा में खाद का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष स्टॉक भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा गया है।

बीज उपलब्धता की स्थिति भी संतोषजनक बताई जा रही है। धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के लिए गुणवत्तायुक्त बीजों का पर्याप्त संग्रहण किया गया है। अधिकांश बीज किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं तथा शेष भंडार आगामी मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। इससे बोवनी कार्य में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। संयुक्त संचालक कृषि गोपिका गभेल ने बताया कि खरीफ फसलों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन स्टॉक, आपूर्ति और वितरण की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, सत्यापन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली जैसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।उन्होंने किसानों से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने तथा आवश्यकता के अनुरूप ही उर्वरक खरीदने की अपील की है। विभाग का लक्ष्य प्रत्येक किसान तक समय पर संसाधन पहुंचाना है। पर्याप्त भंडारण, सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था और सतत निगरानी के कारण दुर्ग संभाग में खरीफ 2026 के दौरान खाद और बीज की किसी भी प्रकार की कमी की संभावना नहीं है।

बालोद में मिशन अंकुर की शुरुआत: 3.5 लाख सीड बॉल से बढ़ेगी हरियाली, कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने किया शुभारंभ

न्यूज रुटीन @ बालोद।

पर्यावरण संरक्षण और जिले में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन बालोद द्वारा एक अभिनव पहल ₹मिशन अंकुर₹ की शुरुआत की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने अभियान का शुभारंभ करते हुए आमजनों को सीड बॉल वितरित किए और उन्हें खाली स्थानों, पहाड़ियों, जंगलों तथा बंजर भूमि पर इन्हें फेंककर पौधारोपण अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल,

दुर्ग वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, जिला पंचायत सीईओ सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सीड बॉल मिट्टी, खाद और विभिन्न उपयोगी वृक्षों के बीजों से तैयार की गई एक

छोटी गेंद होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे लगाने के लिए गड्ढा खोदने या विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें जंगलों, खाली जमीनों, पहाड़ियों और बंजर क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है। मानसून की बारिश के साथ ये बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेते हैं और समय के साथ वृक्ष बन जाते हैं। मिशन अंकुर के तहत स्थानीय प्रजातियों जैसे नीम, पीपल, बरगद, मुनगा, करंज, कटहल और इमली के बीजों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर सीड बॉल तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 2 लाख 50 हजार सीड बॉल तैयार किए गए हैं, जबकि वन विभाग ने 1 लाख सीड बॉल बनाए हैं। इस प्रकार कुल 3 लाख 50 हजार सीड बॉल अभियान के लिए तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने जल संरक्षण के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा सोखता गड्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिले में जनसहभागिता से 3 लाख 50 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया गया था। इस वर्ष भी हरियाली बढ़ाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जिले में 2 लाख 25 हजार से अधिक ट्रेंच का निर्माण कराया गया है, जिससे पौधों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन में मदद मिलेगी।

कलेक्टर ने कहा कि घरों और आसपास उपलब्ध फलों व वृक्षों के बीजों को फेंकने के बजाय उन्हें सुखाकर मिट्टी में लपेटकर सीड बॉल तैयार किए जा सकते हैं। इन सीड बॉल को खाली भूमि पर फेंकने से बारिश के दौरान वे अंकुरित होकर पौधों में बदल जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से हजारों सीड बॉल तैयार हो सके हैं। साथ ही जनदर्शन में पहुंचे लोगों को सीड बॉल वितरित कर उन्हें मिशन अंकुर में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल ने भी लोगों को वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीड बॉल जैसी सरल तकनीक के माध्यम से आम नागरिक भी हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि वृक्षारोपण के दो प्रभावी तरीके हैं—एक पौधे लगाना और दूसरा सीड बॉल के माध्यम से बीजों का रोपण। उन्होंने कहा कि सीड बॉल वर्षा के पानी के संपर्क में आते ही अंकुरित होकर पौधों और बाद में वृक्षों का रूप धारण कर लेते हैं। कार्यक्रम में बिहान समूह की महिलाएं और बड़ी संख्या में जनदर्शन में पहुंचे नागरिक उपस्थित रहे। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि मिशन अंकुर के माध्यम से जनसहभागिता बढ़ेगी और आने वाले वर्षों में बालोद जिले में हरियाली का दायरा और अधिक विस्तृत होगा।

'वन विभाग को रोशन' करने वाले को मिला 'अंधेरा'

दफ्तर चमकाने वाले मैकेनिक का 1.56 लाख डकार गए 'साहब'!

ट्रांसफर होते ही 'रेंजर' और 'SDO' ने बदला रंग.

फोन उठाना बंद, व्हाट्सएप पर भी किया किनारा..

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़

भ्रष्टाचार और सरकारी बाबूशाही जब अपनी औकात पर उतरती है, तो एक आम गरीब मैकेनिक के पसीने की कमाई भी सरकारी तिजोरियों और साहबों की नीयत के बीच दम तोड़ देती है। ताजा और बेहद शर्मनाक मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के वन मंडलाधिकारी (DFO) डिवीजन ऑफिस का है। जिस मैकेनिक ने दिन-रात एक करके, करंट का खतरा मोल लेकर वन विभाग के दफ्तरों, DFO बंगले और SDO बंगले को अपनी मेहनत से रोशन किया, आज वही मैकेनिक मनोज जायसवाल अपनी ही पाई-पाई के लिए कड़कड़ाती धूप में इन दफ्तरों की धूल फांक रहा है। कुल 1,56,570 का भुगतान दबाकर बैठे वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की पोल तब खुली, जब पानी सिर से ऊपर चला गया और पीड़ित ने कलेक्टर की 'जनदर्शन' अदालत में न्याय की भीख मांगी।

फिल्मी स्टाइल में खेला गया टालमटोल का खेल

कटेली ग्राम के रहने वाले पीड़ित बिजली मैकेनिक मनोज जायसवाल ने अपनी शिकायत में जो आपबीती सुनाई है, वह सरकारी सिस्टम के चरित्र को बेनकाब करती है।

साल 2023: पीड़ित ने डिवीजन ऑफिस, DFO और SDO बंगले में बिजली फिटिंग का काम किया। बिल बना 1,72,350, लेकिन 'राजू सिदार रेंजर' ने सिर्फ 59,000 देकर बाकी रकम बाद में देने का झुनझुना थमा दिया। साल 2024-25 मे इसके बाद साहबों ने फिर काम कराया। प्रथम तल, बाबू क्वार्टर, टमटोरा रेस्ट हाउस में AC फिटिंग और रिपेयरिंग के काम जोड़कर कुल बिल 2,85,570 तक पहुंच गया।

कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा भुगतान?

पीड़ित को अब तक महज 1,29,000 ही दिए गए। जब मैकेनिक ने तत्कालीन SDO चंद्राकर और अजय रेंजर से अपने बाकी पैसे मांगे, तो वे जून-जुलाई 2025 तक टालते रहे। जैसे ही दोनों का ट्रांसफर हुआ, साहबों की नीयत बदल गई। अब वे न फोन उठाते हैं और न ही व्हाट्सएप मैसेजों का कोई जवाब देते हैं।

सरकारी दस्तावेज खुद चिल्ला रहे हैं साहबों की मक्कारी!

कलेक्टर जनदर्शन की फटकार के बाद वन विभाग ने 'अधीक्षक, गोमर्डा अभयारण्य सारंगढ़' से जांच कराई। अधीक्षक ने 22.12.2025 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा

शिकायतकर्ता मनोज जायसवाल द्वारा कार्यों का संपादन किया गया था। किन्तु तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारियों की लापरवाही, टालमटोल से आज दिनांक तक उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।₹

बड़ा सवाल–जब विभाग खुद मान रहा है कि मैकेनिक ने काम किया और अधिकारियों ने लापरवाही की, तो उन दोषी अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर उनके वेतन से रिकवरी क्यों नहीं की गई?

'दोषी अफसरों से वसूली' का झांसा देकर केस रफा-दफा करने की इतनी हड़बड़ी क्यों?

इस पूरे मामले में वन विभाग की नीयत पर सबसे बड़ा और तीखा सवाल तब खड़ा होता

है, जब वन मंडलाधिकारी कार्यालय द्वारा कलेक्टर को भेजे गए पत्र क्रमांक/शिका./5745 (दिनांक 26/12/2025) को देखा जाए। एक तरफ विभाग कहता है कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से नियमानुसार वसूली करके मैकेनिक को भुगतान किया जाएगा। लेकिन, इसी पत्र के आखिरी पैराग्राफ में विभाग कलेक्टर से गुहार लगा रहा है कि इस प्रकरण को नस्ती बद्ध (फाइल क्लोज) किया जाए और जनदर्शन के पोर्टल से विलोपित (डिलीट) कर दिया जाए।

जनता पूछती है

जब तक गरीब मैकेनिक के बैंक खाते में उसकी पूरी बकाया राशि (1,56,570) ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक फाइल बंद करने की इतनी छटपटाहट क्यों है?

क्या 'जनदर्शन पोर्टल' से शिकायत को डिलीट कराने के पीछे का मकसद उच्च अधिकारियों की चमड़ी बचाना और मामले को ठंडे बस्ते में डालना है?

क्या ट्रांसफर हो चुके 'साहबों' के रसूख के आगे विभाग घुटने टेक चुका है?

साहबों के बंगले रोशन, गरीब के घर में अंधेरा

सरकारी विभागों में छोटे ठेकेदारों और मजदूरों का भुगतान अटकाना एक आम बीमारी बन चुका है। साहब AC की हवा खाते हैं और मैकेनिक अपने खून-पसीने की कमाई के लिए दफ्तर के बाबू से लेकर कलेक्टर तक के चक्कर काटता है। अगर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने इस मामले में केवल 'कागजी फाइल' बंद करने का खेल खेला, तो यह न्याय का कत्ल होगा। मनोज जायसवाल को आश्वासन नहीं, उसका पूरा पैसा ब्याज समेत मिलना चाहिए, और 'लापरवाह' अफसरों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए।

अधिकारी मिडिया का नहीं उठाते फोन

अनुविभागीय अधिकारी (SDO) अंकित पांडेय द्वारा मीडिया का फोन न उठाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उस सामंती और बेलगाम 'साहब संस्कृति' का हिस्सा है जहां अधिकारी खुद को जनता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ऊपर समझने लगते हैं। जब जनता के सवालों का जवाब देने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है, तो ये 'साहब' अपने कमरों में दुबक कर फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझते।

मीडिया का फोन न उठाना सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि अधिकारी के पास इस महाघोटाले और गरीब के शोषण पर पर्दा डालने के अलावा कोई ठोस जवाब नहीं है। यह केवल एक फोन कॉल को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के मुंह पर करारा तमाचा है।

उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को इस गंभीर उदासीनता और वीआईपी रवैये का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता के प्रति इतनी बेरुखी दिखाई जाएगी, तो आम आदमी का इस सड़ चुके सिस्टम से भरोसा उठना तय है। क्या कलेक्टर महोदय ऐसे गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की इस 'चुप्पी' पर नकेल कसेंगे, या फिर मौन रहकर इस शहशाही रवैये को अपनी मूक सहमति देंगे?

पोस्ट ऑफिस बना अवैध चार्जिंग स्टेशन, सरकारी बिजली का दुरुपयोग

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़

सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का एक मामला सामने आया है। जिले के उप डाकघर सारंगढ़, पिन 496445 के परिसर को डाक विभाग के अधिकारी ने अवैध इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया है। सरकारी बिजली के मीटर से निजी वाहनों को चार्ज कर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पोस्ट ऑफिस में लगे सरकारी कनेक्शन से EV बाइक-स्कूटी चार्ज की जा रही हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि विभाग से इसकी कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई है और न ही व्यावसायिक कनेक्शन कराया गया है।

राजस्व को चूना, नियमों की अनदेखी -बिजली विभाग के नियमों के अनुसार सरकारी कनेक्शन का निजी/व्यावसायिक उपयोग अपराध है। इससे एक तरफ शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया, दिनभर पोस्ट ऑफिस के बाहर गाड़ियां चार्ज होती हैं। मीटर सरकारी है, बिल भी सरकार भरेगी, ये सरासर सरकारी बिजली का दुरुपयोग है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पवनी स्वास्थ्य केंद्र का NQAS मूल्यांकन

हर्बल गार्डन से लेकर प्रसव कक्ष तक, राष्ट्रीय टीम ने परखी पवनी PHC की गुणवत्ता

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पवनी स्वास्थ्य केंद्र का NQAS मूल्यांकन संम्पन

न्यूज रुटीन @ पवनी

NQAS (राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक एश्योरेंस) स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं का राष्ट्रीय स्तर के मानक का मूल्यांकन है जिसके तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू का पदभार ग्रहण करते ही जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन करने के निर्देश दिए हैं । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुष्पेंद्र वैष्णव ने लगातार पिछले कुछ दिनों से जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को NQAS अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित कर तैयारी कराएं हैं । जिला सलाहकार कृष्ण पुरी गोस्वामी के निगरानी में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का NQAS अनुरूप उन्नयन का कार्य चल रहा है ।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवनी का कार्य पूर्ण होने पर NQAS मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया । स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नामित राष्ट्रीय मूल्यांकन कर्ता डॉ सुशील हरिपंत देशमुख पुणे और डॉ योगिता तुलसियन अहमदाबाद के द्वारा 15 और 16 जून को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवनी का भ्रमण किया गया ओपीडी,आईपीडी प्रसव कक्ष, लैबोरेट्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सामान्य प्रशासन जैसे अहम शाखाओं का मूल्यांकन किया गया । मूल्यांकन के दौरान इन शाखाओं से संबंधित रजिस्टर्ड एवं रिकॉर्ड की जांच की गई एवं कार्यक्रमों से संबंधित शाखा के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ भर्ती मरीजों का इंटरव्यू लेकर भी स्वास्थ्य सेवाओं में दी जाने वाली गुणवत्ताओं का मूल्यांकन किया गया । मूल्यांकन के द्वारा हर्बल गार्डन, बीएमडब्ल्यू, फायर सेफ्टी, स्टोर रूम, जननी सुरक्षा योजना, मरीजों की परिवहन, मरीजों को दी जाने वाली पोषण आहार, पेयजल स्त्रोत, आईपीडी में भर्ती मरीजों के लिए बेड एवं बेडशीट, उनकी स्वच्छता, अलग-अलग दिवसों के लिए अलग-अलग रंगों की बेडशीट, प्रयोगशाला में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जांच एवं परीक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में टीबी, कुष्ठ, नेत्र, मलेरिया, फाइलेरिया, NCD, दंत, कान नाक गला इत्यादि कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्नों के साथ-साथ उनके रिकॉर्ड का भी अवलोकन कर मूल्यांकन टीम द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके कुछ दिन पश्चात परिणाम घोषित होंगे । NQAS मूल्यांकन कराने में डॉ शशि जायसवाल बीएमओ बिलाईगढ़, डॉ कविता बंजारे, वीरेंद्र कुर्रे, दीपक धारा डीपीएम, जिला लेखा प्रबंधक मनोज साहू, प्रभारी विकाश खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक लकेश्वर बघेल सहित पवनी स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारीगण और जिला एवं विकास खंड स्तर पर कार्यरत विभिन्न शाखा जैसे चिरायु, कुष्ठ, टीबी, एड्स, नेत्र,एनआरसी, स्टोर इत्यादि शाखा के अधिकारियों, कर्मचारियों का सहयोग रहा ।

मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल

बालोद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन

- मुख्य वक्ता रहे **नारायण चंदेल**
- **विकसित भारत 2047 का संकल्प**
- भाजपा ने गिनाई **12 साल की उपलब्धियां**

- भारत आर्थिक, सामरिक और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है।
- सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं, सेना का मनोबल बढ़ा है।
- भाजपा सरकार विजन के साथ काम करती है, 2047 तक विकसित भारत हमारा लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ निर्माण का श्रेय भाजपा को : चंदेल

अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लिया था। भाजपा सरकारों ने विकास को नई गति दी है।

12 साल बेमिसाल : विकास, विश्वास और जनकल्याण की यात्रा

मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा देश : नारायण चंदेल

न्यूज रुटीन @ बालोद

केंद्र में प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बालोद में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष Narayan Chandel मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष देश के लिए ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरे रहे हैं। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामरिक और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं तथा सेना का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारें लंबे समय तक लागू नहीं कर सकीं। आज भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विश्व नेता के रूप में स्थापित हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला भाजपा अध्यक्ष चेमन देशमुख द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। प्रदेश भाजपा महामंत्री यशवंत जैन ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले की लगभग 25 संस्थाओं से जुड़े प्रबुद्धजनों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा महामंत्री यशवंत जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता यज्ञदत्त शर्मा, पूर्व विधायक खिलावन साहू, प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर, पूर्व विधायक प्रीतम साहू, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू, भाजपा नेता पवन साहू, कृष्णकांत पवार, लेखराम साहू, प्रमोद जैन, राकेश यादव, सौरभ लूनिया, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ निर्माण का श्रेय भाजपा को : चंदेल

नारायण चंदेल ने अपने संबोधन में कहा कि अलग Chhattisgarh राज्य के निर्माण का निर्णय Atal Bihari Vajpayee के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लिया था। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद भाजपा

सरकारों ने विकास को गति दी और वर्तमान में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नए विकास आयाम छू रहा है। चंदेल ने कहा कि भाजपा सरकार दीर्घकालिक दृष्टि और स्पष्ट विजन के साथ काम करती है। इसी सोच का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते हैं और संगठन एक परिवार की तरह कार्य करता है। उन्होंने कोरोना काल का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश को प्रभावी ढंग से संभाला और संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने संबोधन में नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। उन्होंने Abrogation of Article 370 का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने वह निर्णय लिया जिसे लंबे समय तक असंभव माना जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि Ram Mandir Ayodhya का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाया और भारत की विदेश नीति ने देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रबुद्धजनों का सम्मान भी किया गया। सम्मानित व्यक्तियों में ब्रह्माकुमारी विजय लक्ष्मी दीदी, वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश देशमुख, पुरुषोत्तम देशमुख, कवि अशोक आकाश और मनोहर नाहटा प्रमुख रहे।

कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष कमलेश सोनी, रवि प्रकाश पांडे, जितेंद्र साहू, राकेश यादव छोटू, कमल पनपलिया, हरीश कटझरे, प्रेम साहू, संजय शर्मा, अश्वनी यादव तथा दुर्गानंद साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजक प्रमोद जैन ने आभार प्रदर्शन किया।

बिजली दर वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन

सारंगढ़ में कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला, किसानों और आम जनता पर बोझ बढ़ाने का आरोप

सारंगढ़। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ी हुई बिजली दरों को जनविरोधी और किसान विरोधी बताते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी की स्थिति भी निर्मित हुई।

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद पटेल, उत्तरी जांगड़े, जिला पंचायत सदस्य बिनोद भारद्वाज सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय दुबे, सूरज तिवारी, पुरुषोत्तम साहू, अरुण मालाकार, घनश्याम मनहर, रविंद्र नंदे, नीतिश बंजारे और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई वृद्धि से आम जनता, किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि विद्युत श्रेणी में प्रति यूनिट दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों का मासिक बजट प्रभावित होगा। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों से किसानों की खेती की लागत में भी इजाफा होगा, जिससे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से बिजली दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने तथा घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली दर वृद्धि वापस लेने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झूमाझटकी भी देखने को मिली।

सीएमएचओ डॉ. पुष्पेंद्र वैष्णव के एरियर भुगतान पर उठे सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग!

कोषालय अधिकारी बिलाईगढ़ की भूमिका पर भी उठे सवाल, गड़बड़ी हुई तो होंगे जिम्मेदार !

सीएमएचओ सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉ पुष्पेंद्र वैष्णव पर पद के दुरूपयोग का लगा आरोप !

जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र वैष्णव के वेतन एरियर भुगतान को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है, जिसमें वर्ष 2019-20 की लंबित राशि का भुगतान वर्ष 2022 में किए जाने पर पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़-बिलाईगढ़

जिले के वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. पुष्पेंद्र वैष्णव के वेतन एरियर भुगतान को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई है, जिसमें सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के वेतन का भुगतान दिसंबर 2022 में एरियर के रूप में किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत-कर्ता ने इस पूरे प्रकरण को संदिग्ध बताते हुए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार डॉ. पुष्पेंद्र वैष्णव वर्ष 2019-20 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक का उनका वेतन किसी कारणवश लंबित रहा। आरोप है कि उक्त छह माह के वेतन का भुगतान लगभग ढाई वर्ष बाद दिसंबर 2022 में एरियर के रूप में किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी शासकीय कर्मचारी के लंबित वेतन के भुगतान के लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया, सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेजी औपचारिक-ताओं का पालन किया जाता है, लेकिन इस मामले में पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस समय उक्त एरियर राशि का आहरण किया गया, उस समय डॉ. वैष्णव स्वयं खंड चिकित्सा अधिकारी सह आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के पद पर पदस्थ थे। ऐसे में यह सवाल उठाया गया है कि क्या उन्होंने अपने ही लंबित वेतन के भुगतान से संबंधित प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई थी। यदि ऐसा हुआ है तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता और वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से जांच का विषय बनता है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि किसी अधिकारी द्वारा अपने ही वित्तीय प्रकरण से जुड़े निर्णयों या भुगतान प्रक्रियाओं में शामिल होना हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

मामले में तत्कालीन कोषालय अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि शासकीय धनराशि का भुगतान विभिन्न स्तरों की जांच एवं सत्यापन के बाद ही संभव होता है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि लंबित वेतन के भुगतान हेतु कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, किस स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा भुगतान किस नियम एवं आदेश के आधार पर किया गया। यदि समस्त प्रक्रिया नियमों के अनुरूप हुई है तो संबंधित अभिलेख सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि कर सकते हैं, वहीं यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

शिकायत में यह मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक वेतन लंबित रहने का वास्तविक कारण क्या था, भुगतान में हुई देरी के लिए कौन जिम्मेदार था, दिसंबर 2022 में एरियर भुगतान किन प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमतियों के आधार पर किया गया तथा क्या भुगतान प्रक्रिया में शासन के वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया था या नहीं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और न ही संबंधित अधिकारियों का पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने आया है। इसलिए पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक हलकों में इस प्रकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है तथा जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं।

महासमुंद में बाल श्रम का खुलासा, वर्णिका शर्मा के एक्शन से 6 बच्चों का रेस्क्यू

महासमुंदः छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बाल श्रम का खुलासा हुआ है. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा की सक्रियता से 6 बच्चों का सफल रेस्क्यू किया गया. ये सभी बच्चे बैंड पार्टी के साथ श्रम के लिए ले जाए जा रहे थे. छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा महासमुंद के दौरे पर थे. इसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक पिकअप वाहन में कुछ बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में जाते देखा. पूछताछ करने पर पता चला कि बैंड पार्टी द्वारा छह नाबालिग लड़कों को काम के लिए ले जाया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. वर्णिका शर्मा स्वयं करीब आधे घंटे तक मौके पर मौजूद रहीं और पूरे घटनाक्रम की निगरानी करती रहीं.

डॉक्टर वर्णिका शर्मा का एक्शन-वर्णिका शर्मा ने तत्काल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (एसजेपीयू), जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीओ) को तलब किया. तीनों टीमों को मौके पर बुलाया गया. उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया. अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सभी छह बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित तुमगांव थाना पहुंचाया. बाल श्रम में इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन के ड्राइवर तथा संबंधित बैंड पार्टी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. इस पूरे मामले में बाल अधिकार संरक्षण नियम, 2005 की धारा 13 और धारा 14 के तहत संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बाल श्रम जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चाइल्डलाइन और संबंधित विभागों को लगातार निगरानी एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो. बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें श्रम में लगाना कानूनन अपराध है. बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम उन्मूलन के लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है- डॉक्टर वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बचपन सुरक्षित बनाने की मुहिम-डॉ वर्णिका शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक होकर आगे आना होगा, ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित रह सके. बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर मिल सके. इस कार्रवाई को जिले में बाल अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है.

बलरामपुर में रेत माफिया पर एक्शन, 6 ट्रैक्टर जब्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

बलरामपुरः कोरिया में रेत विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर कांड के बाद छत्तीसगढ़ में रेत के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है. बलरामपुर में रेत माफिया के खिलाफ रविवार को जिला प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है. यहां रेत का अवैध उत्खनन करते 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. इसके साथ ही खनिज अधिनियम के तहत भी आगे कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन ने कही है.

सेंदुर नदी में रेत का अवैध उत्खनन-बलरामपुर कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व की टीमें नदियों, नालों में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस दौरान सेंदुर नदी से अवैध रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. खनिज विभाग ने ट्रैक्टर जब्त करने के बाद सभी ट्रैक्टरों को जिला प्रशासन को सौंप दिया है. खनिज विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

बलरामपुर में रेत माफिया पर कार्रवाई-खनिज अमले ने मितगई गांव में सेंदुर नदी से अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की है. यहां से कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. इसके अलावा पिपरौल में अवैध रेत उत्खनन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है. सभी वाहनों को पुलिस को सौंप दिया गया है.

खनिज अधिनियम के तहत लिया गया एक्शन-खनिज अधिकारी राहुल गुलाटी ने मीडिया को बताया कि अवैध रेत उत्खनन के दौरान जब्त किए गए सभी वाहनों के स्वामियों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई है. अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान संचालित रहेगा. खनिज अधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि जिले में अगर कहीं भी खनिज और रेत का अवैध उत्खनन दिखता है तो तुरंत खनिज विभाग को सूचित करें.

भारत के फेफड़े पर चल रही कुल्हाड़ी, खतरे में है बस्तर का हरा दिल

रायपुर। 31 मार्च 2026 को बस्तर को वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किए जाने के बाद से, विशेषकर छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र के नारायणपुर जिले में सड़क निर्माण, वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने, पेंदा अर्थात झूम खेती (कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा परंपरागत रूप से अपनाई जाने वाली स्थानांतरित अथवा शिफ्टिंग खेती की पद्धति), के नाम पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र साफ कर पेड़ों को जलाने जो इस पारंपरिक प्रथा के वास्तविक पात्र नहीं हैं, तथा इमारती लकड़ी की तस्करी के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की गतिविधियों में तेजी आने संबंधी लगातार सूचनाएँ एवं प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। आधुनिक जेसीबी, डोजर एवं अन्य भारी मशीनों से प्राकृतिक वनों को तेजी से साफ किया जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 50 से 70 हेक्टेयर (0.50 से 0.70 वर्ग किलोमीटर) वन क्षेत्र विभिन्न कारणों से नष्ट किया जा रहा है। इन गतिविधियों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। लगभग 5000–6000 वर्ग किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ मध्य भारत के सबसे बड़े सतत वन क्षेत्रों में से एक है और पूरे भारत के भी सबसे बड़े शेष बचे प्राकृतिक वन क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। यह विशाल वन क्षेत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण अबूझमाड़ भारत के फेफड़ों के समान एक अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। साथ ही यह छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, बाघ, तेंदुआ, भालू तथा अनेक अन्य दुर्लभ वन्यजीवों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है।

सिंघवी ने कहा कि अबूझमाड़ का आज तक विधिवत भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसी कारण यहाँ यह अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं कि कौन-सी भूमि राजस्व विभाग की है और कौन-सी वन विभाग की। वर्तमान में भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के टी.एन. गोदावर्मन प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक रूप से वन क्षेत्र प्रथम दृष्टया डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में आते हैं। इसी आधार पर अबूझमाड़ का विशाल प्राकृतिक वन क्षेत्र भी प्रथम दृष्टया डीम्ड फॉरेस्ट है। इसके बावजूद अनेक स्थानों पर भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से पहले ही सड़क निर्माण एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों के लिए बड़ी संख्या में परिपक्व वृक्षों की कटाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास का विरोध नहीं है, परंतु भूमि सर्वेक्षण पूरा होने तथा भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट होने से पहले इस प्रकार की गतिविधियाँ भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट एवं कानूनी विवाद उत्पन्न कर सकती हैं। उस समय तक परिपक्व प्राकृतिक वनों का जो नुकसान हो चुका होगा, उसकी भरपाई किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी।

वन अधिकार अधिनियम को लेकर फैली अफवाह

सिंघवी ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों के बीच यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यदि 31 मार्च 2026 से एक वर्ष के भीतर जंगल काटकर उस पर कब्जा कर खेती प्रारंभ कर दी जाए तो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उस भूमि का पट्टा मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 13 दिसंबर 2005 या उससे पूर्व का कब्जा तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए उससे पूर्व लगातार तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) का निवास एवं वन पर

निर्भरता सिद्ध करना अनिवार्य है। आधुनिक सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग तकनीक के युग में यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि किसी भूमि पर वास्तविक कब्जा कब से है। इसलिए आज जंगल काटकर नया कब्जा करने से किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इसी अफवाह के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। सिंघवी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि यदि एक भी मामले में कार्रवाई की जाए तो ऐसे सैकड़ों अथवा हजारों मामलों में कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे व्यापक असंतोष उत्पन्न हो सकता है तथा भूमि सर्वेक्षण भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वन विभाग के एक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि इन क्षेत्रों में रेंजर, डिप्टी रेंजर एवं वनरक्षक तक पदस्थ नहीं हैं, जिसका कुछ लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

अबूझमाड़ बचाने के लिए दिए सुझाव

1. अबूझमाड़ के अनसर्वेक्षित क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण पूर्ण होने तक वृक्षों की कटाई वाले सड़क एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों पर तत्काल रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्थानीय भाषाओं में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर स्पष्ट किया जाए कि 13 दिसंबर 2005 के बाद किए गए किसी भी नए कब्जे पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।
3. वन कटाई, अवैध लकड़ी तस्करी तथा नए अतिक्रमणों को रोकने के लिए वर्तमान में उपलब्ध डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के बल की प्रभावी सहायता ली जाए।

चर्चा में सिंघवी ने कहा कि अबूझमाड़ केवल छत्तीसगढ़ की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की प्राकृतिक धरोहर है। यदि आज इस वन संपदा को बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। राज्य शासन को ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए कि राज्य की जनता यह सोचने को मजबूर हो जाए कि जब अबूझमाड़ अशांत था तब उसके जंगल अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित थे और अब, जब क्षेत्र में शांति स्थापित हो रही है, वही जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं।

बस्तर के 'ऑपरेशन मास्टर' पी. सुंदरराज अब NIA में IG, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गौरव का क्षण

जगदलपुर। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों को नई दिशा देने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी P. Sundarraj को देश की प्रमुख जांच एजेंसी National Investigation Agency (NIA) में इंस्पेक्टर जनरल (IG) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों का प्रमुख चेहरा

छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी पी. सुंदरराज की पहचान राज्य के सबसे अनुभवी और रणनीतिक पुलिस अधिकारियों में होती है। बस्तर रेंज के आईजी के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों का प्रभावी नेतृत्व किया। उनकी रणनीति केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने स्थानीय आदिवासी समुदायों के साथ संवाद और विश्वास बढ़ाकर कम्युनिटी पुलिसिंग को भी मजबूत किया।

कृषि की पढ़ाई से IPS तक का सफर

मूल रूप से Coimbatore के रहने वाले पी. सुंदरराज का जन्म 27 फरवरी 1980 को हुआ। उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी की और वर्ष 2003 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बने। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया।

पूरा नाम
पी. सुंदरराज (P. Sundarraj)

बैच
2003 बैच IPS

कैडर
छत्तीसगढ़

जन्म
27 फरवरी 1980
गृह नगर
कोयंबटूर, तमिलनाडु

शिक्षा
बी.एससी. एग्रीकल्चर

विशेषज्ञता
नक्सल विरोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा, कम्युनिटी पुलिसिंग

नया दायित्व
IG, NIA

छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए सम्मान

राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एनआईए में पी. सुंदरराज की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए सम्मान और गर्व का विषय माना जा रहा है। बस्तर में उनके नेतृत्व, अनुभव और सुरक्षा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए यह जिम्मेदारी उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। उनकी सफलता राज्य के युवा पुलिस अधिकारियों और सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

आसमान में उड़ता ड्रोन और सुधरती तकदीर

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़

कहते हैं कि अगर हौसलों को सही तकनीक और अवसरों के पंख मिल जाएं, तो ग्रामीण परिवेश की साधारण सी दिखने वाली महिलाएं भी कामयाबी की नई उड़ान भर सकती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक छोटे से गांव खोरीगांव की रहने वाली सुनीता पटेल की। सुनीता आज सिर्फ अपने घर की दहलीज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आसमान में ड्रोन उड़ाकर अपने खेतों को समृद्ध बना रही हैं और खुद 'लखपति दीदी' बनकर ग्रामीण सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश कर रही हैं।

शुरुआत एक सपने की, जिसने बदली जिंदगी

इस बदलाव की नींव तब पड़ी जब 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ₹नमो ड्रोन दीदी₹ योजना की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद देश की ग्रामीण महिलाओं को तकनीक से जोड़कर उनकी सालाना आय को 1 लाख रुपये से ऊपर ले जाना था। सुनीता पटेल ने इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। दिसंबर 2023 में वे अपने सपनों की पोटली बांधकर 15 दिनों के कड़े प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर गईं। वहां उन्होंने न सिर्फ ड्रोन उड़ाने की बारीकियां सीखीं, बल्कि खेतों में कीटनाशकों और नैनो उर्वरकों के सही इस्तेमाल का तकनीकी ज्ञान भी हासिल किया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उन्हें उर्वरक कंपनी 'इफको' (IFFCO) की ओर से कृषि ड्रोन मिला, तो मानो उनकी आजीविका को नए पंख मिल गए।

खेतों में तकनीक की क्रांति और 2 लाख रुपए तक की आय

साल 2024 से शुरू हुआ सुनीता का यह सफर आज 2026 में सफलता के शिखर पर है। सुनीता अब हर साल खेतों में दवा और खाद का छिड़काव करके 1 से 2 लाख रुपये की सम्मानजनक वार्षिक आय कमा रही हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सुनीता अपने काम को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं मानतीं। ग्रामीण परिवेश से जुड़ी होने के कारण वे अमीर-गरीब का भेद किए बिना, पैसों की

परवाह किए बगैर हर किसान के खेत में उतनी ही शिद्दत से काम करती हैं। शनिवार को सारंगढ़ मंडी प्रांगण में जब 'खेती बचाओं अभियान' और 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला' का आयोजन हुआ, तो सुनीता के हुनर को देखने भारी भीड़ उमड़ी। वहां मौजूद प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के सामने जब सुनीता ने पानी से भरे भारी-भरकम ड्रोन को रिमोट के जरिए आसमान में उड़ाया और मैदान में छिड़काव का सजीव प्रदर्शन किया, तो पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। मंत्री जी ने भी उनके इस जज्बे और तकनीकी कुशलता की जमकर सराहना की।

कैसे काम करती है यह योजना और आप कैसे उठा सकते हैं लाभ?

सुनीता की यह सफलता दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की ताकत को दर्शाती है। इस योजना के तहत देश की सात प्रमुख उर्वरक कंपनियां महिलाओं को ट्रेनिंग और ड्रोन सप्लाई में मदद कर रही हैं।

अगर गांव की कोई भी अन्य महिला सुनीता की तरह 'ड्रोन दीदी' बनना चाहती है, तो उसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वह कम से कम 10वीं पास हो और किसी पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य हो। चयन होने के बाद नजदीकी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) में 15 दिनों की मुफ्त पायलट और असिस्टेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद DGCA द्वारा आधिकारिक 'रिमोट पायलट सर्टिफिकेट' मिलता है। ड्रोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी दी जाती है। बाकी बची रकम पर भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के जरिए महज 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन मिल जाता है।

प्रेरणा की नई मिसाल

आज सुनीता पटेल सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे जिले और पड़ोसी राज्यों की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। शासकीय कार्यक्रमों में जब वे अपने ड्रोन के साथ पहुंचती हैं, तो उन्हें देखकर सैकड़ों अन्य ग्रामीण महिलाओं की आंखों में भी आत्मनिर्भर बनने के सपने तैरने लगते हैं। सुनीता ने साबित कर दिया है कि भारत के गांवों की तरक्की का रास्ता अब खेतों से होते हुए आसमान की तरफ जाता है। यदि योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://namod-ronedidi.da.gov.in/ पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।

सुहेला क्षेत्र गढ़ रहा प्रगति के नए आयाम, हर समस्या का प्राथमिकता से होगा समाधान:मंत्री टंक राम वर्मा

न्यूज रुटीन @ रायपुर

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा अपने जिला प्रवास के दौरान रविवार को तहसील सुहेला के ग्राम आमाकोनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 10 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन तथा 18 लाख रुपए की लागत से तैयार प्रार्थना शेड एवं अहाता निर्माण का लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सुहेला क्षेत्र में अब विकास के कार्य लगातार गति पकड़ रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाएगा।

समग्र विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित-राजस्व मंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। हमने जनता से की गई 'मोदी की गारंटी' के सभी प्रमुख वादों को पूरा कर दिया है।

3 से 4 वर्षों में हर परिवार को मिलेगा पक्का आशियाना-ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देते हुए श्री वर्मा ने बताया कि वर्तमान में आमाकोनी ग्राम में 51 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में और भी आवास स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अगले 3 से 4 साल के भीतर क्षेत्र में कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। सरकार हर घर में शुद्ध पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने से हर परिवार में खुशहाली आएगी। उन्होंने ग्रामीणों से आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहकर गांव के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। लोकार्पण समारोह के इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य,जनपद सदस्य, सरपंच सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

सारंगढ़ में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा

सारंगढ़ बिलाईगढ़. राजस्व, आपदा प्रबंधन पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा के मुख्य आतिथ्य में कृषि उपज मंडी परिसर सारंगढ़ में जिला स्तरीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगो योगा 365 डेज एम्ब्रेस योगा और ₹बढ़ते उम्र के स्वास्थ्य के लिए योग₹ इस वर्ष का थीम था। इसमें जिले के जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, स्कूल, कॉलेज, भारत स्काउट,

जूनियर रेडक्रॉस, एनएसएस आदि के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। योग की शुरुआत भगवान श्री धनवंत्री और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया। योग शिक्षक के रूप में व्यायाम शिक्षिका ममता साहू के द्वारा सभी को योग करवाया गया। इसके बाद सिम्मी योगा एंड फिटनेस सेंटर के बच्चों ने सामूहिक योग प्रदर्शन, योगाचार्य सुभाष पटेल की टीम द्वारा सामूहिक प्रदर्शन, सरिया के योगिनी अकादमी द्वारा श्रीरामचंद्र सहित अन्य गीतों पर सामूहिक प्रदर्शन किया। साक्षी पटेल ने एकल गीत में योग प्रदर्शन की। मुख्य अतिथि ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ राष्ट्र बनाने के सन्देश का वाचन किया और सभी नागरिकों क़ो योग की बधाई दिए। इस दौरान राजस्व मंत्री ने योग के सभी प्रदर्शन करने वाले दल, जनप्रतिनिधि के साथ सामूहिक फोटो खिचवाया। इस

रूस से स्पेन तक योग दिवस की धूम, पीएम मोदी ने वैश्विक सहभागिता की सराहना की

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनियाभर के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योग आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के उद्देश्य से जोड़ रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में कहा, "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 को एक सच्चे वैश्विक उत्सव का रूप देने के लिए दुनियाभर के लोगों का हार्दिक आभार। यह देखकर खुशी होती है कि योग अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की साझा भावना के साथ अलग-अलग देशों और हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ रहा है।" उन्होंने कहा कि कामना है कि यह दिन और अधिक लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करे। इस साल 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' रखी गई है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि योग हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, बढ़ती उम्र में योग एक उपयोगी अभ्यास हो सकता है क्योंकि यह लोगों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। योग में हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, सांस लेने की तकनीक

और ध्यान शामिल होते हैं, जो शरीर का संतुलन, लचीलापन, ताकत और चलने-फिरने की क्षमता बेहतर करने के साथ-साथ तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

रूस में, मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र ने मॉस्को सिटी सरकार के सहयोग से प्रतिष्ठित लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के यूनिव-र्सिटेत्स्काया स्क्वायर में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष का विषय था 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग'। जर्मनी में, ऐतिहासिक ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने भारतीय दूतावास, बर्लिन और टैगोर सांस्कृतिक केंद्र ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से अंतर-राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने बताया, "कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है।" इसी तरह हंगरी में बुडापेस्ट के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रॉयल पैलेस और प्लाजा डी ओरिएंते की शानदार पृष्ठभूमि में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया।

स्वदेशी ताकत से समुद्र में बढ़ेगी भारत की पावर

कोलकाता शिपयार्ड में तैयार हुआ आधुनिक युद्धपोत 'आईएनएस दूनागिरी'

कोलकाता स्थित शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के आधुनिक युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेवल डिजाइन ब्यूरो के अधिकारियों तथा जहाज से जुड़े कमांडिंग और इंजीनियरिंग स्टाफ ने बताया कि स्वदेशी तकनीक और डिजाइन क्षमता के बल पर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेवल डिजाइन ब्यूरो के कैप्टन मनीष प्रकाश ने बातचीत में कहा कि यह जहाज पूरी तरह भारत में कल्पित, डिजाइन और निर्मित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में युद्धपोत डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में देश की स्वदेशी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा पिछले 15 महीनों के दौरान इसी श्रेणी के कई जहाज नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। इसी क्रम में पी-17ए श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी को नौसेना में शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

इंजीनियरिंग पहलुओं पर जानकारी देते हुए इंजीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष ने बताया कि इस जहाज में आधुनिक प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी गतिशीलता और संचालन क्षमता बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक जहाज की गति और नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाती है। आईएनएस दूनागिरी की कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन दिव्या आलोक ने कहा, "पी-17ए श्रेणी के जहाजों के नाम पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं। इस दृष्टि से दूनागिरी भी हमारी सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से जुड़ा हुआ है।"

एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर ऋषभ ने कहा कि कुछ ही वर्षों में डिजाइन चरण से पूर्ण युद्धपोत तक पहुंचना भारत की जहाज निर्माण क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने बताया कि यह जहाज मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध (एंटी-सबमरीन वारफेयर) के लिए तैयार किया गया है और समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों की पहचान तथा निगरानी करने में सक्षम है। जहाज के कैप्टन कमांडर सुनील मल्होत्रा ने बताया कि छोटे आकार के बावजूद इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगे हैं। इसमें स्वदेशी सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, टॉरपीडो ट्यूब और डिकॉय सिस्टम शामिल हैं, जो इसे समुद्री खतरों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कमांडर दीक्षित मन्नन ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन जहाजों में 80 प्रतिशत से अधिक उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी हैं। पावर जनरेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम सहित अधिकांश महत्वपूर्ण तकनीक भारतीय उद्योगों द्वारा विकसित की गई है।" उन्होंने कहा कि जहाज में अत्याधुनिक संचार प्रणाली भी लगी है,

लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत: सीएम योगी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, पीएम मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

राजधानी लखनऊ में सोमवार को अलीगंज क्षेत्र के पुरनिया में एक एनीमेशन कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। घटना में 15 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में जुटी रहीं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। एमएस-102 अलीगंज सेक्टर-डी स्थित हेड एंड हॉपर्स एनीमेशन एंड गेमिंग जोन दूसरी मंजिल पर स्थित है। दोपहर ढाई बजे के करीब यहां आग लग गई। बताया जाता है कि एसी का कंप्रेशर फटने से यह घटना हुई। आग लगने के बाद पूरे भवन में धुआं भर गया। इससे अंदर मौजूद छात्रों में भगदड़ मच गई। कई छात्रों ने जान बचाने के लिए से छलांग लगा दी। इससे वह घायल हो गए। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और राहत की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बगल के घर की छत से कोचिंग की दीवार काटकर रेस्क्यू का प्रयास किया गया। करीब 10 लोगों को रेस्क्यू कर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहीं आग और धुएं की वजह से 15 की मौत हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। अलीगढ़ का दौरा रद्द कर राजधानी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी अफसरों से ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निकांड में मृतकों व घायलों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये व घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है।

न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर भारत ने जीता खिताब हॉकी इंडिया ने किया प्राइज मनी का ऐलान

भारत ने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने आज रविवार को खिताबी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की। इस कामयाबी पर हॉकी इंडिया ने प्राइज मनी का ऐलान किया है।

नवनीत कौर ने भारत के लिए पहला गोल किया

मुकाबले के चौथे मिनट में नवनीत कौर ने भारत के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद सुनीलिता टोप्पो (15वें मिनट) ने

दूसरा गोल दागा। टीम ने शानदार डिफेंसिव खेल दिखाते हुए जीत हासिल की और खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही अगले सीजन के एफआईएच हॉकी महिला प्रो लीग में अपनी जगह भी पक्की कर ली। फाइनल में लालरेम्सियामी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला, जबकि दीपिका छह गोल के साथ टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रहीं; उन्होंने यह सम्मान यूएसए की एशले सेसा के साथ साझा किया।

भारत की दूसरी नेशंस कप जीत

यह भारत की दूसरी नेशंस कप जीत है। इससे पहले उन्होंने साल 2022 में हुए पहले टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी। भारत इस इवेंट में अजेय रहा और पूल-ए के मुकाबलों में यूएसए (3-2), जापान (2-1) और उरुग्वे (3-2) को शिकस्त दी थी। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में चिली के खिलाफ 6-0 से हराया। फाइनल में, उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीता। रविवार को फाइनल मैच की शुरुआत में मेजबान टीम का बॉल पर ज्यादा कब्जा रहा और वे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, मेहमान टीम ने पहला बड़ा मौका तब बनाया जब नवनीत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला। उन्होंने चौथे मिनट में एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ इस सेट-पीस से गोल किया और भारत को बढ़त दिलाई।

भारत ने ट्रांजिशन में शानदार खेल दिखाया

भारत ने ट्रांजिशन में शानदार खेल दिखाया और अपनी ऊर्जा से न्यूजीलैंड के डिफेंस के लिए कई मुश्किलें खड़ी कीं। उन्होंने पहले क्वार्टर में मिले पांचवें पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी बढ़त बढ़ाई। 15वें मिनट में सुनीलिता टोप्पो ने दीपिका के तेज शॉट को दिशा देकर स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अनुशासित खेल जारी रखा, जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी लय हासिल की और वापसी की कोशिश की। मेहमान टीम को भी अंतर कम करने के कुछ मौके मिले, लेकिन कोई भी टीम दोबारा गोल नहीं कर सकी, जिससे हाफटाइम तक भारत के पास दो गोल की बढ़त बरकरार रही।

तीसरे क्वार्टर में भारत ने मजबूती बनाए रखी और जबरदस्त डिफेंस का प्रदर्शन किया, जिससे मेजबान टीम गोल करने का कोई स्पष्ट मौका नहीं बना सकी। उनके तेजतर्रार खेल ने न्यूजीलैंड के डिफेंस से गलती करवाई, लेकिन नवनीत के रिवर्स शॉट को गोलकीपर ने रोक लिया। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड को पेनाल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि, सविता ने उस सेट-पीस को बचा लिया और भारत की दो गोल की बढ़त बनाए रखी। मेहमान टीम ने अपने अनुशासित डिफेंस का शानदार प्रदर्शन जारी रखा और आखिरकार 2-0 से जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया।

हॉकी इंडिया नकद इनाम की घोषणा की

टीम की इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए, हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों के लिए 1.5 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "शान, आभार और सम्मान।

टीम इंडिया की एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप 2025-26 खिताब जीत का सम्मान करते हुए, हॉकी इंडिया हर खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान करता है। उस टीम के लिए एक सही इनाम जिसने देश का मान बढ़ाया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं, दूरस्थ बस्तियों में लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को उनके निवास क्षेत्र के समीप ही जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं, बच्चों तथा बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है तथा जरूरतमंद लोगों को आगे के उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ा जा रहा है।इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र अखइनकोना में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहाड़ी कोरवा परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर के दौरान 53 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा 35 मरीजों को आवश्यक दवाइयां प्रदान की गईं। साथ ही शिशुवती माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष निगरानी कर उन्हें पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इन शिविरों से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किसी भी व्यक्ति तक आवश्यक सेवाएं पहुंचें और विशेष रूप से दूरस्थ एवं कमजोर वर्गों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उनके गांवों के निकट ही उपलब्ध कराई जा सकें। इसी उद्देश्य से राज्यभर में स्वास्थ्य शिविरों और जन-जागरूकता गतिविधियों का संचालन लगातार किया जा रहा है।

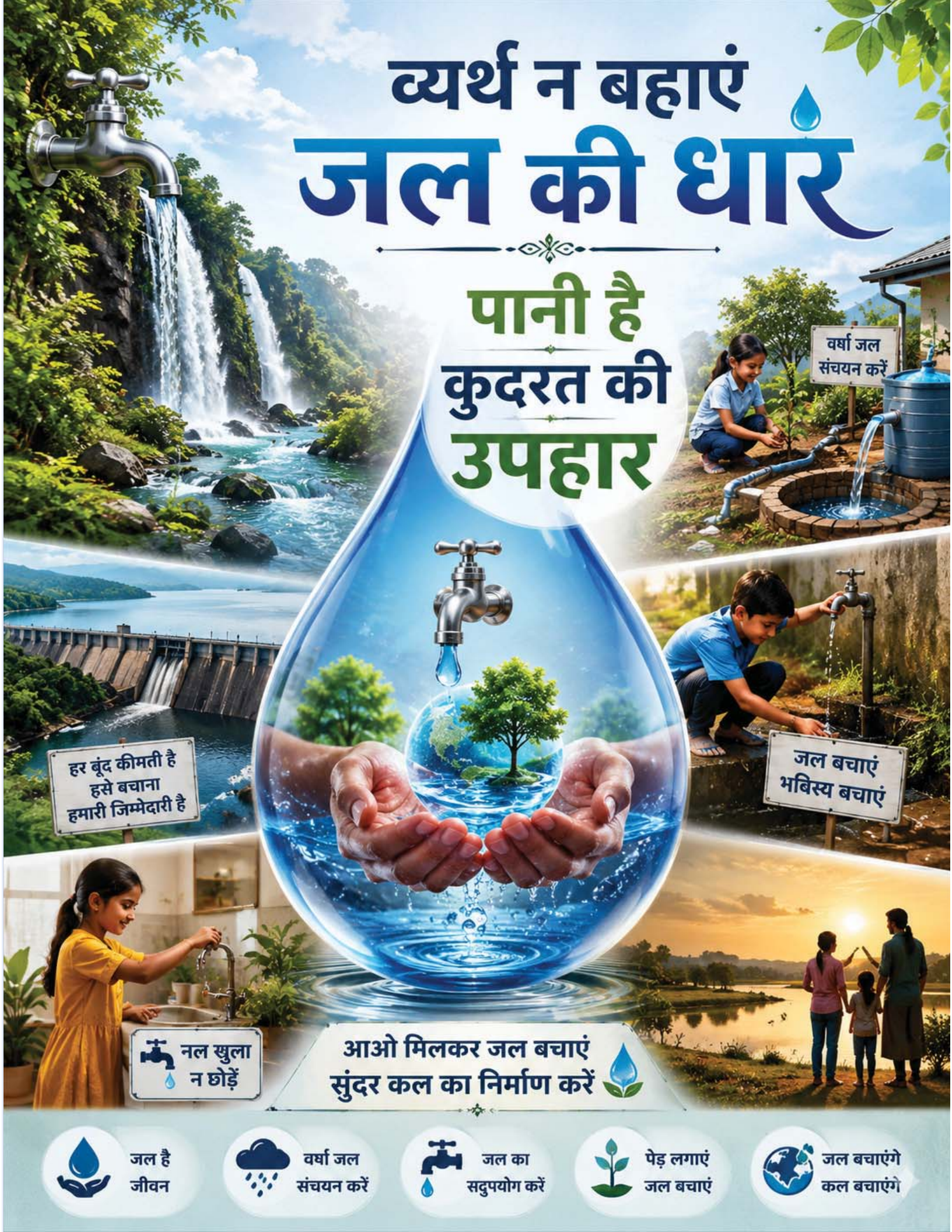
व्यर्थ न बहाएं
जल की धार
पानी है
कुदरत की
उपहार
वर्षा जल
संचयन करें
हर बूंद कीमती है
इसे बचाना
हमारी जिम्मेदारी है
जल बचाएं
भविस्य बचाएं
नल खुला
न छोड़ें
आओ मिलकर जल बचाएं
सुंदर कल का निर्माण करें
जल है
जीवन
वर्षा जल
संचयन करें
जल का
सदुपयोग करें
पेड़ लगाएं
जल बचाएं
जल बचाएंगे
कल बचाएंगे